फाइनैन्शल कोलैबोरेशन कहां से लाया जाय। यह उस की उपलब्धता पर निर्भर है और उस के औचित्य पर निर्भर है कि कितना अच्छा है और कहां से मिलता है।

Shri M. K. Kumaran: May I know what is the amount so far spent on this project and how far the land acquisition and other preliminary works have progressed?

Shri Raj Bahadur: The amount that has been spent so far has been spent on the acquisition of land. 64 acres of land has been acquired. We are also going to reimburse the cost of diversion of road which is Rs. 13,40,176.

Shri P. Kunhan: May I know whether the Government has received any offer from West Germany; and, if so, what steps the Government have taken with regard to that?

Shri Raj Bahadur: I said, Sir, that we have received an offer, through an Indian firm, from the West German Ship-building yard and we have invited them to come and negotiate with us.

Power from Rihand Project

\+

*651. **Shri Bhagawat Jha Azad:**
Shri Bhakt Darshan:
Shri Utiya:

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state the attempts that have been made by the Central Government to reach an early settlement over the distribution of power generated from the Rihand Project between U.P. and Madhya Pradesh?

The Parliamentary Secretary to the Minister of Irrigation and Power (Shri S. A. Mehdi): The desirability of arriving at an early settlement in the matter has been impressed on the two State Governments from time to time. The matter is receiving their attention.

Shri Bhagwat Jha Azad: May I know whether in the past the Central Government has been able to persuade the two sister governments to sit round a table and discuss the past agreement as well as the future one arising out of it?

Shri S. A. Mehdi: There have been two Zonal Councils in 1958 and 1960. The first one appointed a committee and the second asked the Chief Ministers to settle the matter. The Chief Minister of Uttar Pradesh had given a date in last May, but due to certain factors it was postponed. It is expected that they will soon meet and settle the matter between themselves.

Shri Bhagwat Jha Azad: Could we have any idea as to the availability of surplus power from this according to the terms of the agreement?

Shri S. A. Mehdi: That could only be settled after the Chief Ministers have settled their own dispute.

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान्, क्या यह सत्य है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने बार बार मध्य प्रदेश सरकार को और केन्द्रीय सरकार को यह बात सूचित की है कि अभी जो बिजली पैदा हो रही है वह उत्तर प्रदेश की आवश्यकता के लिये भी पूरी नहीं है और आगे चल कर जब बिजली अधिक पैदा होगी तब ही बटवारा करना उचित होगा?

श्री सै० अ० मेहदी : अभी तो यू० पी० के चीफ़ मिनिस्टर साहब ने यह कहा है कि वे मध्य प्रदेश के चीफ़ मिनिस्टर साहब से मिल कर इस पर बात चीत करेंगे और उस के बाद कोई चीज तय हो सकती है।

डा० गोविन्द दास : क्या यह बात सही नहीं है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों सरकारें भारत सरकार के अन्तर्गत हैं? जब दोनों में मामला निपट नहीं रहा है और इतने दिनों से पड़ा हुआ है तो क्या यह उचित नहीं होगा कि केन्द्रीय सरकार दोनों मुख्य मंत्रियों को बुला कर अपने सामने इस का निपटारा करवा दे?

The Minister of Irrigation and Power (Hafiz Mohammad Ibrahim):

May I remind the hon. Members, Sir, that there was a discussion very recently on this matter in this House and at the end of that discussion when I replied to the debate I said that I would personally intervene and persuade both the Chief Ministers to come round to a certain agreed view. But since then—it was not long ago, it is a recent happening—up till now, I wrote two letters, but on account of this circumstance or that circumstance the two could not meet. So I again say that as far as the Central Government is concerned, what it can do it will do and it shall do.

श्री सिंहासन सिंह : क्या यह सही है कि यह रिहन्द डैम की स्कीम उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र की तरक्की के लिये ओरिजिनली सोची गई थी, और आज बिजली बनने के बाद भी उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में इस बिजली का एक अंश भी नहीं गया है ?

हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम : इस बात की तो, हुजूर, यह है कि यह आइडिया था जिस वक्त रिहन्द डैम को अख्त्यार किया गया था, लेकिन उस के बाद रिहन्द डैम तैयार होने से पहले ही तीन पावर हाउसेज उस एरिया में, जिस के मुताल्लिक अभी मेरे दोस्त ने जिक्र फरमाया है, बना दिये गये थे, और उस एरिया में पहले ही बिजली मिलनी शुरू हो गई थी । इस के लिहाज से उतनी स्ट्रिक्ट पोजीशन कायम नहीं है, जितनी कि मेरे लायक दोस्त कहते हैं । लेकिन इस के मतलब यह नहीं है कि यू पी० को हम महरूम कर देंगे ।

Shri Vidya Charan Shukla: May I know whether the electricity to be generated from the first phase of the Rihand project has already been committed? If so, what amount of electricity will be made available to Madhya Pradesh after the agreement has been finalised? Is there any surplus electricity still available?

The Minister of State in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Alagesan): As an interim measure the power that will be generated by Rihand project has been promised to DVC and other areas where it is immediately needed. That will be only as a temporary measure. The UP Government are prepared to hand over 10 per cent of the power to Madhya Pradesh. As soon as the talks are over and agreement is reached, it will be possible to give power from Rihand to Madhya Pradesh. There is no question of its being taken away from them.

Shri Mohammad Elias: In view of the acute shortage of power in West Bengal, may I know whether the Government has taken any decision to give some.....

Mr. Speaker: Order, order.

Shri Mohammad Elias: There were discussions between the West Bengal and the UP Governments and I only want to know whether any decision has been taken to give some more power to West Bengal from the Rihand project.

Mr. Speaker: Order, order.

Shri Mohammad Elias: Sir, I am asking this question because it is in connection with the Rihand project.

Mr. Speaker: Order, order. He will very kindly resume his seat. Shri Sarjoo Pandey.

श्री सरजू पाण्डेय: अभी माननीय मंत्री जी ने बतलाया है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिये रिहन्द डैम के पूरा होने से पहले ही बिजली मिलने लगी । तो क्या मैं जान सकता हूं कि रिहन्द डैम से कोई बिजली पूर्वी उत्तर प्रदेश को नहीं दी जायेगी ?

हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम : यह बिल्कुल गलत है । कौन कहता है कि उसे बिजली नहीं दी जायेगी । जितनी जरूरत होगी वह उसे भी दी जायेगी और दूसरे जरिये से भी पैदा कर के दी जायेगी ।

That area will not be ignored. All the requirements of that area shall be met either from Rihand or from somewhere else.

Shrimati Savitri Nigam: How many kilowatts of power have been given to the Bundelkhand area and the Eastern Districts of Uttar Pradesh from the Rihand project?

Mr. Speaker: He has answered that. Shri Yadav.

श्री रामसेवक यादव : पूर्वी उत्तर प्रदेश की हालत बहुत खराब है जिस की एक बार इस सदन में चर्चा भी उठी थी और प्रधान मंत्री ने उत्तर प्रदश सरकार को लिखा है। तो क्या इस दृष्टिकोण को सामने रखत हुए उत्तर प्रदेश को ज्यादा बिजली देने की कोई व्यवस्था है?

अध्यक्ष महोदय : इस का जवाब दे दिया गया है ।

आयुर्वेदिक तथा यूनानी दवाइयें

*६५२. **श्री विभूति मिश्र**: क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि आयुर्वेदिक तथा यूनानी दवाइयों के निर्माण को संविहित नियंत्रणाधीन लाने में क्या प्रगति हुई है?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : यह विषय अभी विचाराधीन है ।

The matter is still under consideration.

अध्यक्ष महोदय : इतना सब समझते हैं । "विचाराधीन है," या "पटल पर रख दिया गया है" इस को दोहराने की जरूरत नहीं है ।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में वैद्यों और हकीमों से कोई राय अब तक ली है?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : जी हां, इस पार काफी विचारविनिमय हुआ है और जो आयुर्वेदिक रिसर्च कौंसिल है उस के सामन भी वह तजवीज़ गई है। स्टेट गवर्नमेंटस के पास भी भेजी गई है। सोलह स्टेट गवर्नमेंटस के जो जवाब आये हैं उन में से चौदह ने कहा है कि इस की अत्यन्त आवश्यकता है और यह होना चाहिये, एक ने कहा है कि पहले आयुर्वेदिक कोपिया बनाया जाय उस के बाद कन्ट्रोल लगाया जाय, और एक ने कहा है कि इस से कोई फायदा नहीं होगा ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने सवाल यह किया था कि वैद्यों और हकीमों की राय भी ले ली गई है या नहीं ।

डा० सुशीला नायर : मैं ने अर्ज किया कि उन के सामने भी यह चीज रक्खी गई है और उन्होंने भी कहा है कि कुछ कन्ट्रोल होनी तो चाहिये। कुछ दिक्कतें हैं, उन की भी उन्होंने चर्चा की है ।

श्री विभूति मिश्र : क्या यह सही है कि वैद्यों और हकीमों से सरकार ने राय ली है, लेकिन जो रस वाली चीज़ें बनाते हैं, उस की पावर के बारे में सरकार वैद्यों और हकीमों पर ज्यादा नियंत्रण रखती है जब कि ऐलोपैथिक के लोगों पर इस प्रकार का नियंत्रण नहीं है?

डा० सुशीला नायर : ऐसी कोई बात नहीं है । हकीकत यह है कि बहुत सी दवायें आयुर्वेद से बनाई जा रही हैं । उन के ऊपर इस वक्त किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है, इस चीज के बारे में कि वह सचमुच जो मूल पदार्थ होने चाहियें उन का इस्तेमाल करते हैं या नहीं या दवाइयों को हाइजीनिक कंडिशन्स में तेयार किया जाता है या नहीं । और आज तो आयुर्वेद में इंजक्शन भी बन र हैं, वे इंजक्शन्स भी हाईजीनिक तरीके से बनते हैं या नहीं, इस पर भी कोई नियंत्रण नहीं है । और श्रीमान्, आज आयुर्वेद में बहुत सी दवाइयां बन रही हैं जिनमें लोग एलोपैथी की भी कुछ दवाइयां डाल लेते हैं जिनकी लिस्ट लम्बी है, और इस बिना पर किये आयुर्वेदिक दवाइयां हैं वे सारे प्रतिबन्धों से मुक्त हो जाती हैं । इस परिस्थिति को दुरुस्त करना चाहिए ऐसी सब की राय है ।

Shri Rameshwar Tantia: The hon. Health Minister said that there is no control on the pharmacopoea of